



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 338 राँची, बुधवार 30 वैशाख, 1937 (श०)
20 मई, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

13 मई, 2015

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक- 27/विकास दिनांक 06 जनवरी, 2008
 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०- 2776 दिनांक 28 अप्रैल, 2009
 3. श्री ए०के० पाण्डेय, राज्यपाल के तत्का० प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची-सह-संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन पत्रांक- रा०स०-124/पी०एस० (गो०) दिनांक 07 मई, 2012
 4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 8119 दिनांक 12 जुलाई, 2012 एवं पत्रांक- 10061 दिनांक 31 अगस्त, 2012
 5. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 8223 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012
-

संख्या-5/आरोप-1-403/2014 का.-4280-- श्री मनमोहन प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 2091/99, गृह जिला- नवादा, बिहार), कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक- 27/विकास दिनांक 06 जनवरी, 2008 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है ।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

(क) श्री प्रसाद द्वारा अपने पदस्थापन के दौरान योजनाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता था जिसके कारण प्रखण्ड के विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन एवं गुणवत्ता सही ढंग से संचालित नहीं हो रही थी। चुरचू प्रखण्ड के अन्तर्गत नरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण योजनाओं की जांच में निम्न त्रुटियाँ पाई गई:-

(i) सिंचाई कूप निर्माण योजनाओं में पंचायत इन्दा, हेसालोंग, हुआग, जरबा, हेसागढ़ा में कूप निर्माण की योजनाओं में कार्य से अधिक मापी किया गया, काम के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया एवं कार्यपूर्ण होने पर भी मापी नहीं ली गई ।

(ii) 20' (फिट) व्यास कूप निर्माण का जोड़ाई कार्य मिट्टी से किया पाया गया जबकि प्राक्कलन के अनुसार कूप का जोड़ाई कार्य प्रारम्भ में 10' (फिट) मिट्टी से एवं शेष सीमेंट से कराये जाने का प्रावधान है। चुरचू प्रखण्ड में कलस्टर कूप निर्माण में महज खाना-पुरी की गई और वैसे लाभुक जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, उन्हें भी कलस्टर कूप दिया गया। कूप का निर्माण कलस्टर में न होकर पूरे गाँव के विभिन्न स्थानों में किया गया। कूप का निर्माण खेत में न करके घर के आँगन में किया गया जिससे सिंचाई का काम नहीं लिया जा सकता ।

(ख) श्री प्रसाद द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों यथा पंचायत सेवक एवं कनीय अभियंता के माध्यम से नरेगा के विभिन्न लाभुकों से कमीशन के रूप में नाजायज राशि वसूला जाता था ।

(ग) श्री प्रसाद की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण तापस सोरेन के ईलाज एवं मृत्यु के उपरान्त मुआवजा आदि का भुगतान करना पड़ा जिसके कारण सरकारी राशि का व्यय हुआ ।

उक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0- 2776 दिनांक 28 अप्रैल, 2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री ए0के0 पाण्डेय, राज्यपाल के तत्का0 प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जांच प्रतिवेदन पत्रांक- रा0स0-124/पी0एस0 (गो0) दिनांक 07 मई, 2012 द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से सीधे तौर पर किसी आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया है, परन्तु आरोप पत्र में बतायी गई त्रुटियों के

लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नाते इन्हें जवाबदेह बताया गया है। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को आरोप सं0-(क) (i) एवं (ii) के लिए दोषी माना गया ।

तदुसार तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के प्रस्तावित दण्ड की सूचना के साथ संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक- 8119 दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई है। इसके अनुपालन में श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2012 एवं पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2012 द्वारा समर्पित किया गया ।

श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में आरोपों को नकारते हुए निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया:-

- (i) मनरेगा अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त सीमांत कृषकों को भी सिंचाई कूप देय है।
- (ii) मनरेगा अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति को मात्र सिंचाई के लिए ही नहीं, अन्य कार्य (पेयजल आदि) हेतु भी कूप दिया जा सकता है ।

उक्त बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक- 10061 दिनांक 31 अगस्त, 2012 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्रतिवेदन की मांग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्रांक- 8223 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 द्वारा उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई ।

श्री मनमोहन प्रसाद के विरुद्ध प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

- (i) सोक पिट्स एवं रीचार्ज पिट्स के रूप में अनुसूचित जाति/जनजाति घरों/बाड़ी में सिंचाई कूप स्वीकृत हो सकते हैं किन्तु उनके प्राक्कलनों की विशिष्टियाँ सिंचाई कूप जैसी नहीं होंगी। आरोप सं0-(क) (ii) में वर्णित कूप सिंचाई कूप हैं। अतएव ये निश्चित तौर पर सोक पिट एवं रीचार्ज पिट नहीं हैं। इनके घरों में इन कुओं के स्थल चिह्नित किये जाने का औचित्य नहीं है ।
- (ii) सीमांत कृषकों के रूप में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति को भी योजनायें स्वीकृत होंगी तो उनके स्थल सीमांत कृषकों को जिन प्रयोजनों के लिए कुएँ दिये जाते हैं उनके ही अनुरूप होंगे ।
- (iii) एक लाभुक भुनेश्वर रविदास के घर में पहले से कुएँ थे, उनसे 10' हटकर योजना अन्तर्गत कूप का निर्माण कराया गया है ।

(iv) स्पष्टतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में स्थल चयन में बरती गई त्रुटियों का आरोप श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रमाणित होते हैं। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन इन त्रुटियों को कम करने में सक्षम नहीं है।

अतः आरोप सं0- (क) (i) एवं (ii) में श्री प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों, जो प्रमाणित पाये गये हैं, के लिए विभागीय संकल्प सं0 13920, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनपर इनकी तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि उन्होंने सोक पीट्स एवं रिचार्ज पीट्स नहीं दिया है, बल्कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को नरेगा के मार्गदर्शिका के अनुसार सिंचाई कूप दिया है। श्री प्रसाद ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभुकों के जमीन उपलब्धता के बारे में अंचल अधिकारी, चुरचू से प्रतिवेदन की माँग की। अंचल अधिकारी, चुरचू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लाभुकों के पास निम्नरूपेण भूमि है-(i)श्री भिखू करमाली-1.19 एकड़, (ii)श्री शंकर रविदास-0.40 एकड़, (iii)श्रीमती सुनीता देवी- 2.13 एकड़, (iv) श्री मुनेश्वर रविदास-0.37 एकड़, (v) श्री नरेश रविदास-0.13 एकड़।

श्री मनमोहन प्रसाद के अनुसार नरेगा अधिनियम, 2005 के दिशानिर्देश की कंडिका-5.1 (क) स्वीकार्य परियोजनाएँ के 5.11 के क्रमांक-4 में स्पष्ट निदेश है कि अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों अथवा इन्दिरा आवास के लाभान्वितों की जमीन तक सिंचाई की सुविधा पहुँचाना।

श्री प्रसाद के अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक-3469, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से पृच्छा की गई कि वैसे कूप जो लाभुकों के घर में या घर के पास हैं, उनके समीप कृषि योग्य जमीन की उपलब्धता क्या है?

उपायुक्त, हजारीबाग ने पत्रांक-38सी0/विकास, दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सभी सिंचाई कूप के आसपास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कूप को उपयोगी बताया है।

पुनः, विभागीय पत्रांक-11356, दिनांक 26 नवम्बर, 2013 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से कुओं में सीमेंट की जगह मिट्टी से जोड़ाई के लिए कौन दोषी है तथा तापस सोरेन से दस हजार रुपये घूस लेने के लिए कौन जिम्मेवार है? के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, हजारीबाग ने अपने पत्रांक-2सी0/विकास, दिनांक 11 जनवरी, 2014 द्वारा प्रतिवेदित किया कि कुओं में सीमेंट की जगह मिट्टी से जोड़ाई के लिए तदेन कनीय अभियंता, श्री दिनेश कुमार दोषी है एवं श्री तापस सोरेन से रिश्तत लेने के मामले में श्री ब्रज किशोर महतो, पंचायत सेवक दोषी हैं।

श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन एवं उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में योजनाओं के कार्यान्वयन में राशि सही ढंग से विकास कार्य पर खर्च हो एवं प्राक्कलन विशिष्टियों के अनुरूप हो-यह देखना आरोपी पदाधिकारी की प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के रूप में जवाबदेही बनती थी। मनरेगा के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायत-सेवक जिम्मेवार होता है जबकि इसके अनुश्रवण की जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। प्रखण्ड स्तर पर इसका अनुश्रवण सीधे तौर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा ही किया जाता है। जाँच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि सिंचाई कूपों के निर्माण में सीमेंट की जगह मिट्टी का उपयोग किया गया था। यदि श्री प्रसाद द्वारा संबंधित कुछ योजनाओं का ही कार्य के दौरान अनुश्रवण किया जाता तो क्रियान्वयन में निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो पाता। इस प्रकार, निर्माण कार्य के अनुश्रवण करने में लापरवाही के लिए श्री प्रसाद सीधे तौर पर दोषी हैं।

समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के अपील आवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-13920, दिनांक-20 दिसम्बर, 2012 को विलोपित करते हुए इनके विरुद्ध तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 338—50।